(b) and (c). The actual imports were short of sanctioned imports for many reasons. Important of these are :—

1. Inability of foreign suppliers to offer the required quantity of tractors.

2. Time taken in price negotiations with foreign suppliers.

3. Tests of tractors were going on at the Budni Station and imports could not be cleared pending release of test reports.

4. Suspension of imports of remaining quantity of RS—09 tractors.

(d) The programme for the import of tractors against the requirement of 1970-71 is under consideration of Government. Actual import of tractors during the financial year 1971-72 will depend on the programme to be approved and the number of tractors received against orders placed during the previous years.

Setting up of Tobacco Development Board for clearing Stocks of Tobacco in Andhra Pradesh

1771 SHRI M. RAM GOPAL REDDY :
SHRI A. K. GOPALAN :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :—

(a) whether stocks of tobacco have accummulated in Andhra Pradesh ;

(b) whether there has been a demand by the tobacco growers that there should be a Tobacco Development Board to help in clearing the unsold buffer stocks of tobacco ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SINDE) : (a) The present unsold stock of tobacco in Andhra Pradesh is reported to be negligible.

(b) and (c). The Government of India have examined a proposal for setting up a Tobacco Board and have decided that the constitution of a Board is not necessary.

ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास

1772. **श्री जगन्नाथराव जोशी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयुक्त आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित गोष्ठी में यह अनुभव किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए बाजारों की वर्तमान दो हजार की संख्या को बढ़ा कर चौदह हजार करने की अत्यन्त आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा-साहिब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद द्वारा अप्रैल, 1971 में बाजार नगरों तथा क्षेत्र विकास (मार्किट टाउन्स एण्ड कौसल डिवलेपमेंट) के सम्बन्ध में आयोजित विचार गोष्ठी के सन्दर्भ में तैयार किये गये एक पृष्ठभूमि कागजात में बताया गया था कि एक विपणन केन्द्र द्वारा 12 मील व्यास के क्षेत्र में समुचित रूप से सेवा की जा सकती है। 12500 से 14000 बाजार नगरों की आवश्यकता होगी, परन्तु इस कागजात में ही इन आंकड़ों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया था।

पर्याप्त विचार विमर्श के उपरान्त, विचार गोष्ठी अपनी अन्तिम चर्चाओं में इस निर्णय पर पहुंची कि अन्तसंबंधित बाजारों की सुव्यवस्थित शृंखला पहले से ही विद्यमान है। अतः नये बाजारों नगरों की स्थापना की अपेक्षा इन बाजारों को सशक्त बनाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।